International Capital Inflow

912. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:
SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the money paid in 1993-94 and 1994-95 on account of repayment of debts, payment of interest and premature payment of debts separately with details of countries/institutions and what is the estimated payment schedule for the next two financial years;

(b) the details of total inflow of funds during 1993-94 and 1994-95 in terms of loans, international assistance and grants, NRI remittance investments by foreign Investments etc.; and

(c) whether Government have undertaken any study to assess the nature of international capital inflow in terms of speculative and long term investment if so, what are the broad indications and if not, whether and by when Government propose to conduct such a study ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Import duty on the hearing aids

913. SHRI INDER KUMAR GUJRAL : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the import duty on the hearing aids and its components is not in conformity with the Government's policy to help the handicapped persons;

(b) whether representations have been made for abolition of this duty;

(c) if so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) Representations have been received from Hearing Aids Industry to abolish the countervailing duty (CVD) on parts of hearing aids. At present, specified parts of hearing aids are exempt from excise duty if they are used captively in the manufacture of hearing aids. As there is no general exemption from excise duty on parts of hearing aids, the imported parts are leviable to CVD.

(c) In view of the ensuing budget it is not possible to indicate the views of the Government on this matter at this stage.

मुद्रास्फीति और कीमतें

914. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि तथा अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के माहवार आंकड़े क्या रहे ;

(ख) उक्त संतुलन के क्या कारण है ;

(ग) इन महीनों के दौरान करेंसी नोटों और सिक्कों के रूप में जारी की गई कुल राशि कितनी है तथा इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं का अतिलंघन करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) मुद्रास्फीति दर में वृद्धि एवं कीमतों में वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) पिछले वर्ष के दौरान थोक मूल्य सूचकांक द्वारा

यथा-निर्धारित मुद्रास्फीति की दर और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के महीने-वार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

महीना	मुद्रास्फीति दर/ वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत)	
	सभी वस्तुएं	आवश्यक वस्तुएं
अप्रैल, 1993	6.9	5.2
मई . .	6.9	5.2
जून . .	7.0	6.4
जुलाई . .	7.3	6.0
अगस्त . .	8.0	8.2
सितम्बर . .	8.8	11.1
अक्तूबर . .	8.5	12.1
नवम्बर . .	8.6	13.2
दिसम्बर . .	8.8	12.6
जनवरी,94 . . .	9.1	11.4
फरवरी . .	9.5	11.8
मार्च . .	10.5	11.8

(ख) चीनी, कपास और मूंगफली आदि के उत्पादन में कमी, और पिछले लगातार तीन वर्षों से न्यूनतम समर्थन मूल्यों में अधिक वृद्धि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निर्गम कीमतों में परिणामी वृद्धि से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर दबाव पड़ा है। पिछले वर्ष ट्रक मालिकों की हड़ताल और देश के कुछ भागों में पड़े सूखे के कारण भी पिछले वर्ष जुलाई/अगस्त से मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियां बढ़ी हैं।

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 1993–94 के दौरान मुद्रा आपूर्ति (एम० 3) में 66741 करोड़ रुपये (18.2 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिकल्पित 14 प्रतिशत की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक है। मुद्रा आपूर्ति में लक्षित वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक वृद्धि दर मुख्यतः विदेशों से अधिक पूंजी प्रवाह के परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 28775 करोड़ रुपये (115.3 प्रतिशत) के सामयिक विस्तार के कारण हुई।

(घ) सरकार द्वारा हाल ही के महीनों में किए गए मुद्रास्फीति घटाने के उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) पिछले वर्ष 7.3 प्रतिशत (संशोधित अनुमान) की तुलना में वर्ष 1994–95 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय।

(ii) बजट घाटे और वर्ष 1994–95 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से तदर्थ सरकारी हुंडियों के रूप में निवल उधार को 6,000 करोड़ रुपए तक सीमित करना और ऐसा तंत्र शुरू करना जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सीमा निरन्तर 10 दिन के कार्य-दिवसों से अधिक के लिए 3,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो।

(iii) मुद्रास्फीति की वृद्धि में कमी करने की दृष्टि से बैंकों के नकद आरक्षित मुद्रा भण्डार के अनुपात को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना।

(iv) मुक्त सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत शून्य शुल्क सहित चीनी और कपास के आयात की अनुमति देना।

(v) परिष्कृत पामोलीन के आयात को मुक्त सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखना और 20 प्रतिशत के रियायती

शुल्क पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आयात की अनुमति देना ।

(vi) कपास/यार्न आपूर्ति को पूरा करने के लिए रियायती शुल्क पर विस्कोज स्टेपल फाइबर के आयात की अनुमति देना ।

(vii) खाद्यान्न भंडारों के वृहद सरकारी भंडार से भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से चावल और गेहूं की खुले बाजार में बिक्री द्वारा खाद्यान्न बाजार में सक्रिय हस्तक्षेप करना ।

(viii) कृषि से संबंधित कच्चा माल जैसे :—कपास, वनस्पति तेल, तिलहन और दालों के लिए चयनात्मक ऋण नियंत्रण उपाय ।

Establishment of German Banks

915. SHRI S. MUTHU MANI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether three German Banks have approached Government for permission to establish their branches in our country;

(b) if so, whether Government gave its approval for the same;

(c) the details of Indian Banks functioning abroad, Bank-wise, Branch-wise and country wise ; and

(d) whether any more Indian Banks approached Government for permission to open its branches abroad and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY) : (a) and (b) Reserve Bank of India (RBI) has reported that in the recent past Deutsch Bank has been allowed to open a branch in Bangalore and Dresdner Bank has been allowed to upgrade its representative office in Bombay into full fledged Branch. RBI have further stated that BHF Bank Commerz Bank have envinced interest in opening their branches in India. However, no formal application has so far been received from them by RBI.

(c) The Bank-wise, Branch-wise and Country-wise details of Indian bank functioning abroad, as on 1-1-94, are given in the Annexure. [*See* Appendix 172, annexure No. 25]

(d) RBI has reported that the following banks have approached it for opening branches/representative offices in the countries shown against them:—

Name of the Bank	Name of the countries
1. State Bank of India	China and South Africa
2. Punjab National Bank	Singapore and Hongkong
3. Canara Bank	South Africa
4. Bank of Baroda	South Africa
5. Indian Bank	Indonesia

Government dues on Financial Institution

916. SHRI SANJAY DALMIA Will the MINISTER OF FINANCE be pleased to stat:

(a) what is the number of companies in which Financial Institutions like LIC, UTI, IDSI, ICICI, nationalised and commercial banks have 20% —33% and more holding with Govt. dues both direct and indirect held up amounting to Rs. 1,000 crores and more;

(b) what is the role of these institutions in initiating action against